MR. CHAIMAN: Is it the consensus of the House?

SOME HON. MEMBERS: Yes, yes.

MR. CHAIRMAN: So it is accepted.

16.15 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS, 1976-77—*Contd.*

MINSTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND THE DEPARTMENT OF CULTURE—*Contd.*

श्री सुधाकर पांडेय (चन्डौली): सभापति महोदय, शिक्षा मंत्रालय के अनुदान की मांगों का मैं समर्थन करता हूं। विगत कुछ महीनों में कई विश्वविद्यालयों में मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मैंने वहां की परिवर्तित परिस्थिति देखी है। लगता है कि श्मशान में बसंत आ गया है। सर्वत्र शिक्षा के क्षेत्र में छात्र पढ़ने में लगे हुए हैं और अध्यापक पढ़ाने में लगे हुए हैं। जो पुलिस के लोग हैं वे भी शांति का अनुभव कर रहे हैं और इससे ऐसा लगता है कि इंदिरा जी ने जो कदम उठाया था वह सफल सिद्ध हुआ और उसके माध्यम से, जसा विरोध पक्ष के लोग भी चाहते थे कि शिक्षा की व्यवस्था में परिवर्द्धन होना चाहिए, वह श्रीमय होनी चाहिए, उसका मार्ग प्रशस्त हुआ है। इसके लिए मैं प्रधान मंत्री जी को बधाई देता हूं।

शिक्षा मंत्रालय के कार्यों के संबंध में बराबर विचार विनिमय होता रहता है। शिक्षा एक राष्ट्रीय विषय है। लेकिन हमारे देश का यह दुर्भाग्य है कि उसे स्टेट-सबजेक्ट बना दिया गया है। बार-बार इस पर चिन्तन और विचार विनिमय होता रहता है और इस चिन्तन और विचार विनिमय का जो परिणाम होता है, जब शिक्षा मंत्री अपने राज्य में पहुंचते हैं तो उसका कार्यान्वयन नहीं होता। इसका यह परिणाम है कि अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग प्रकार की शिक्षा व्यवस्था चलती रहती है। कोई राज्य किसी विषय में आगे हो जाता है तो कोई राज्य किसी विषय में पीछे हो जाता है। जब देश के सारे शिक्षा-शास्त्री विचार-विनिमय के उपरान्त यह चाहते हैं कि शिक्षा को केन्द्र का समवर्ती विषय बना दिया जाये तो इसको बनाने में कौन सी बाधा है—मैं चाहता हूं प्रोफेसर साहब जब उत्तर दें तो इसको बताने की कृपा करें। (व्यवधान) इसका कार्यान्वयन होना चाहिए। कार्यान्वयन न होने से सचमुच बड़ी हानि हो रही है। यह अवश्य होना चाहिए नहीं तो निश्चित रूप से जो स्थिति वांछित है वह उत्पन्न नहीं हो पायेगी।

अभी कुछ दिनों पहले तक शिक्षा संस्थाओं को साम्प्रदायिकता का अड्डा बना दिया गया था, शिक्षा संस्थाओं को भाषायी अखाड़ा बना दिया गया था, शिक्षा संस्थाओं को राजनीति का अड्डा बना दिया गया था। अब स्थिति सामान्य है किन्तु हमें यह देखकर आश्चर्य होता है कि सी०पी०आई० के श्री चन्द्रप्पन साहब, जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है, चाहते हैं कि यूनियन की राजनीति विश्वविद्यालयों में लौटे। जो काम वहां पर आर०एस०एस० कर रही थी वही काम हमारे मित्र वहां पर करना चाहते हैं। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि जब चुनाव हुआ दिल्ली में, बनारस में या अन्यत्र, आर०एस०एस० के लोग आये वह ठीक नहीं, आपने कहा शिक्षा संस्थाओं में चुनाव की परिपाटी नहीं होनी चाहिए लेकिन जब आर०एस०एस० पर रोक लगाई गई तो आप वही प्रथा अपनाना चाहते हैं ताकि आप वहां पर स्वच्छन्द रूप से विचरण करें और दूसरे न करें—यह बात मेरी समझ में नहीं आती। शिक्षा के किस प्रतिमानीकरण की बात इसके माध्यम से की जाती है क्योंकि

[श्री सुधाकर पांडे]

एक राजनीतिक दल को न घुसने दिया जाये, दूसरे को विश्वविद्यालयों में घुसने दिया जाये, तीसरे को घुसने दिया जाये यह ठीक नहीं है—मैं अपने सभी मित्रों से आग्रह करूंगा कि शिक्षा के जो क्षेत्र हैं उन्हें शिक्षा के क्षेत्र ही रहने दें, वहां पर चरने, खाने और नोचने का कोई यत्न न करें। अगर यही करना है तो उसके लिए जनता काफी है। जनता के बीच में अपनी शक्ति की प्रतिष्ठा स्थापित करें और उसके माध्यम से सत्ता प्राप्त करें तो अधिक उत्तम होगा।

इसके साथ ही विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अच्छा काम कर रहा है किन्तु बार-बार यह कहा जाता है कि राज्यों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाये जाये, शिक्षा मंत्री उसके लिए सहमत भी हो जाते हैं परन्तु शायद ही कुछ राज्य होंगे जहां यह कार्य हुआ है, बाकी स्थानों पर यह कार्य नहीं हुआ है। इसका परिणाम यह होता हैं कि लोग शिकायत करते हैं कि अमुक विश्वविद्यालय को ज्यादा मिल गया, अमुक को कम मिला, अमुक का यह हुआ और अमुक को यह हुआ इसलिए मेरा आग्रह है कि राज्यों के भीतर भी अनुदान आयोग की भांति कोई संस्था बना देनी चाहिए। इसी प्रसंग में मुझे यह भी कहना है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए एक कमेटी बनी थी, प्रोफेसर साहब उसकी प्रगति से भी हम लोगों को अवगत करायेंगे और बतायेंगे कि उसके कार्य की क्या प्रगति चल रही है।

तीसरी बात यह है कि शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषायें बनें, इस दिशा में भारत सरकार ने बहुत कुछ काम किया, राज्यों को करोड़ों रुपये ग्रंथ रचनार्थ दिये। विश्वविद्यालय के जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा पुस्तकें लिखी जाती हैं परन्तु उनके विश्वविद्यालय में ही पाठ्य ग्रंथ के रूप में, जिस पाठ्य ग्रंथ समिति के वे चेयरमैन है, उसमें वे नहीं रखी जाती हैं—यह विडम्बना है? जब कि उनके द्वारा लिखी किताबें दूसरे प्राइवेट पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित होने पर उसी विश्वविद्यालय में पाठ्य ग्रंथ के रूप में रख ली जाती हैं।

राजा राममोहन राय पुस्तकालय का काम बहुत अच्छा चल रहा है किन्तु वहां भेदभाव की नीति बरती जा रही है—इस ओर भी मैं शिक्षा मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। वह भेदभाव की नीति यह है कि अंग्रेजी के साथ विशेष पक्षपात किया जाता है, उसकी पुस्तकों पर कम कमीशन लिया जाता है। इस व्यवस्था को ठीक करना चाहिए। कोई प्रकाशक यदि अपनी किताबें भेजना चाहे तो वह संकट में पड़ जायेगा क्योंकि जिन पुस्तकालयों को किताबें भेजते है उनसे उसको रसीद भी लेनी पड़ेगी और प्रायः पुस्तकालय रसीद नहीं देते हैं, रजिस्ट्री से भेजने के बाद भी रसीद स्कूल, कालेज या पुस्तकालय नहीं भेजते है इसलिये भुगतान नहीं होता। इस व्यवस्था में परिमार्जन और सुधार होना चाहिए और वही कमीशन की दर हिन्दी की पुस्तकों पर भी रहनी चाहिए, अन्य भारतीय भाषाओं की पुस्तकों पर भी रहनी चाहिए जोकि अंग्रेजी भाषा की पुस्तकों पर कमीशन की दरें हैं।

अभी मेरे मित्र कह रहे थे इस देश में शिक्षा का प्रसार कम है। मैं समझता हूं शिक्षा का प्रसार बहुत है किन्तु साक्षरता का प्रचार कम है। इस देश के लोग बहुत ही शिक्षित है—जो जानना चाहते हैं वह इसको जानते हैं। साक्षरता के प्रचार में रुपये की कमी आई है किन्तु केवल रुपये से साक्षरता का प्रचार नहीं होगा। रुपये दीजिए, अभी

आई है उसके लिए विरोध पक्ष भी उत्तरदायी है। विरोध पक्ष के लोगों ने काम में बाधा डाली है, किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया है। मैं कहता हूं जो रुपया उपलब्ध है राष्ट्र के निर्माण के लिए, उसमें से जो अंश शिक्षा को मिल रहा है उसका सही और उचित उपयोग हो तो पहले की अपेक्षा द्विगुणित गति से शिक्षा का, कम से कम विश्वविद्यालय तक की शिक्षा का विकास होगा। इसमें रेडियो और टेलीविजन का योगदान लिया जा रहा है। और मैं समझता हूं कि वह योगदान अधिक अच्छी तरह सफल हुआ है।

शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा के लिये आधारभूत ग्रंथों के निर्माण की योजना बनाई है और इस योजना के अन्तर्गत कई विदेशी भाषाओं के शब्द-कोष के निर्माण का कार्य अपने हाथ में लिया है। यह एक अच्छा कार्य हो रहा है, इसमें तेजी आनी चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी संसार की भाषाओं का कोष भारतीय भाषाओं में आ जाय और भारतीय भाषाओं का कोष संसार की भाषाओं में जाये ताकि हमारे देश की जनता का सम्पर्क सीधे उन देशों से हो सके। इसमें शिक्षा मंत्री महोदय विशेष इन्टरेस्ट ले रहे हैं।

अभी 10+2+3 के नये पैटर्न की बात कही गई है। मैं भी इसका समर्थक हूं, यह पहले ही लागू हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक पूरी तरह से सर्वत्र लागू नहीं हुआ। मैं समझता हूं—यदि जुलाई तक सारे देश में यह लागू हो जाय तो इससे देश का कल्याण होगा और देश की शिक्षा पद्धति में एकरूपता उत्पन्न होगी।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी शिक्षा का स्तर घटा है, उसे बढ़ाने का यत्न करना चाहिए। चाहे यूनीवर्सिटी हो, हायर सैकण्डरी स्कूल हो, इन्टरमीडिएट कालिज हो या कुछ भी हो—अगर शिक्षा का बोझ बढ़ता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन वह फार्मूला लागू होना चाहिए और जल्दी से जल्दी लागू होना चाहिए। भाषा सम्बन्धी सरकार की जो नीति है उसके बारे में जनता में कई सम्भ्रम हैं। मैं चाहूंगा कि इस फार्मूले के सम्बन्ध में भारत सरकार की जो भावी नीति है, उसका विशदतापूर्वक स्पष्टीकरण किया जाय, विवेचन किया जाय ताकि किसी भी प्रकार का कोई भ्रम एक अच्छे कार्य के प्रति जनता में न फैलाया जा सके। मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे मंत्री महोदय भारतीय भाषाओं के उतने ही प्रेमी हैं जितना कोई और हो सकता है। वह अंग्रेजी को लादना नहीं चाहते हैं, लेकिन भारतीय भाषाओं के साथ अंग्रेजी को भी रखना उनकी दृष्टि में अनिवार्य है ताकि देश की खिड़की विदेशी भाषाओं के लिये खुली रहे और वहां से ज्ञान का स्रोत सीधा आता रहे।

हमारे यहां कई एकादमियां हैं, तीन-चार हैं, वे कैसा काम करती हैं, इसके सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। उनके सम्बन्ध में रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट के तेहत काम करने की बात शिक्षा मंत्रालय ने पहले कही थी। उसमें क्या प्रगति हुई है—हम लोग यह जानना चाहेंगे, उसके माध्यम से वह प्रगति कहां तक पहुंची है—आप हमें अपने उत्तर में बतलायें।

हमारी यूनिवर्सिटियों में जो उच्च शिक्षा की व्यवस्था है, उसमें नियुक्तियों के सम्बन्ध में प्रतिमानीकरण का समय अब आ गया है, क्योंकि अब वहां पर नियुक्तियां ठीक ढंग से नहीं हो पा रही हैं। यद्यपि लोग कहते हैं कि इनमें सरकार का वर्चस्व है, परन्तु वास्तविकता यह है कि विभागाध्यक्ष मठाधीश हो गये हैं। वे दूसरी यूनिवर्सिटियों में जाकर वहां के अध्यक्ष के मन के अनुसार काम कर देते हैं और दूसरे लोग इनको यूनिवर्सिटी में आकर इनके मन के अनुसार काम कर देते हैं, परिणाम यह हो रहा है कि यूनिवर्सिटी में जो

[श्री सुधाकर पांडे]

गुणात्मक विकास होना चाहिए वह नहीं हो रहा है और लोगों के चेले-चपाटों की नियुक्तियां हो रही है। यह बडी भयावह स्थिति है। अब समय आ गया है कि हमे इन पर विचार करना चाहिए। पहले अच्छे लोग विश्वविद्यालयों के वाइस-चान्सलर नहीं बनना चाहते थे, लेकिन अब बनना चाहते है और हमे अच्छे लोगों को विश्वविद्यालयों मे वाइस-चान्सलर के रूप मे भेजना चाहिए। पहले मेरी एक-दो लोगों से बात हुई, जब उनसे वाइस-चान्सलर बनने की बात की गई तो कहने लगे —मेरे ऊपर कृपा कीजिये, आप मेरे साथ कौनसी दुश्मनी का बदला निकालना चाहते है। लेकिन अब अच्छे लोग विश्वविद्यालयों मे जाने के लिये तैयार है, इसलिये अच्छे लोगो को वहां भेजना चाहिए और क्या विश्वविद्यालय की नियुक्तियों का केन्द्रीयकरण हो सकता है, इस पर भी विचार करना चाहिए।

आजकल यूनिवर्सिटियों मे जो प्राध्यापक है, उनके लडके प्रथम श्रेणी मे पास होते है। मेरा यह अनुभव है कि जो प्रोफेसर होता है, उसका लड़का प्रथम श्रेणी मे पास होता है, कभी-कभी सर्व-प्रथम भी होता है, रिकार्ड-बीटर भी होता है। यहां पर परीक्षा प्रणाली में सुधार की बात कही जा रही है, यह एक अच्छा कदम है. . .

श्री नाथूराम अहिरवार (टीकमगढ) : इन लोगों की परीक्षा अलग से होती है।

श्री वाई० एस० महाजन (बुलडाना) : ऐसा नहीं हो सकता।

श्री सुधाकर पांडे : लेकिन यदि कोई ऐसा कलंक हमारी शिक्षा प्रणाली पर लगता है, हमारे शिक्षकों पर लगता है—तो यह उचित बात नहीं है। यदि कोई ऐसा निश्चय हो गया हो कि जो हमारे प्रोफेसर होंगे, उनके लड़के प्रथम श्रेणी में ही पास होंगे, ऐसा कोई विधान बन गया है, तब तो मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन जो छात्र वास्तव में मेहनत करता है, जो पढ़ता-लिखता है, जब उसके साथ ऐसी घटना घटती है तो उसका कलेजा टूट जाता है। क्योंकि जो नियुक्तियां होती हैं उनमें प्रथम श्रेणी को वरीयता दी जाती है, वरीयता दिया जाना स्वाभाविक भी है, तब हमारे विश्वविद्यालयों मे जो इस प्रकार की धांधली चल रही है, उनको कैसे रोकेंगे—यह प्रो० नूरुल हसन साहब ही बतला सकते है, क्योंकि वे स्वयं शिक्षा के क्षेत्र के मगरमच्छ रहे है। कृपा कर वे बतलायें कि इन धांधलियों को वे कैसे रोकेंगे।

अब रही—शिक्षा के माध्यम से समसामयिक संस्कृति के लाने की बात। अभी तक तो संस्कृति की बात नहीं थी, ध्वंस की और विनाश की बात होती थी। शिक्षा के माध्यम से उपयोग इस कार्य के लिये किया जाता था कि हम कैसे मूर्तिभंजन कर सत्तारूढ होंगे। आज आवश्यकता इस बात की आ गई है कि राष्ट्रीयता और अपनी समसामयिक संस्कृति क्या है—इसे भलीभांति स्कूलों और कालिजों के माध्यम से समझा जाय। हमारी संस्कृति बिलगाव की नहीं रही है, विविधता मे एकता दिखाने की संस्कृति रही है किन्तु उस विविधता को एकता में पिरोने वाली कोई न कोई चीज जरूर रही होगी और वह चीज यह रही है कि दूसरो को वही देखना जो हम अपने को देखना चाहते है। इस तरह की समतावादी दृष्टि की स्थापना शिक्षा के माध्यम से होनी चाहिए क्योंकि जो शिक्षा के केन्द्र हैं वे केवल साक्षरता के ही केन्द्र न बनें बल्कि आदमी बनाने के केन्द्र बनें। तभी इस देश का कल्याण हो सकता है और तभी सही अर्थों में शिक्षा की स्थापना हो सकती है।

मैं यह मानता हूं कि हमारी जो पुरानी परिपाटी है उस पर भी हमें सोचना चाहिए क्योंकि जो पुराने अध्यापक होते थे, वे चौबीसों घंटे छात्र को अपने साथ रखते थे और वे

काशी के संस्कृत के बहुत से विद्वानों को जानता हूं जो छात्र का खर्चा भी खुद देते थे। वे उनको पढ़ाते थे, मालिश कराते समय पढ़ाते थे और शिक्षकों के जीवन का प्रभाव उन पर पड़ता था किन्तु आज के शिक्षकों के जीवन का प्रभाव अगर शिक्षार्थियों पर न पड़े, तो अधिक अच्छा होगा क्योंकि आज सिनेमा-संस्कृति अपना घर बना करती चली जा रही है। वहा समबंध-सामासिक सस्कृति की स्थापना होनी चाहिए, भारतीय संस्कृति की स्थापना होनी चाहिए, उस अभेद वाली दृष्टि की स्थापना हो जो मनुष्य मात्र और जीव मात्र मे एकता देखती है। इसके लिए गम्भीरता से सोचने का समय आ गया है और इसके सम्बन्ध मे जो सुझाव हैं उन सुझावों के कार्यान्वयन का समय भी आ गया है।

एक बात मैं अन्त मे कहना चाहता हूं और वह यह है कि भारतीय भाषाओं को जब तक शिक्षा का माध्यम नहीं बनाया जाता, तब तक देश का कल्याण नहीं होगा क्योंकि संसार मे जितना ज्ञान, विज्ञान है और दूसरी चीजें है वे सब जनता की सेवा के लिए है। आज भी विश्वविद्यालयों मे आधिपत्य अंग्रेजी का है क्षेत्रीय भाषाओं का भी नहीं है और हिन्दी का भी नहीं। जब तक क्षेत्रीय भाषाएं विश्वविद्यालयों मे नहीं आयेंगी, तब तक ज्ञान की, विज्ञान की धारा जनता तक नहीं पहुंचेगी और इनका उपयोग कुछ वर्गों के लोग ही करते रहेंगे। इस वर्ग को तोड़ने का काम हमें करना चाहिए और क्षेत्रीय भाषाओं के लिए अधिक से अधिक काम करना चाहिए। आज भी बहुत से लोग यह कहते हैं कि पाठ्य ग्रन्थ नहीं बने इसलिए यथास्थिति बनी रहनी चाहिए। यथास्थिति को तोड़ने के लिए यह आवश्यक है कि मंत्री ने कार्य शुरू करा दिया जाये और धीरे-धीरे वह कार्य आगे बढ़ता जाये।

अन्त में मैं शिक्षा मंत्री जी को बधाई देता हूं कि अब की बार पहले से अधिक रुपया शिक्षा कार्यों पर खर्च कर रहे हैं। विरोधी पक्ष के लोगों की अगर कृपा बनी रही तो दिनोंदिन शिक्षा पर अधिक से अधिक रुपया खर्च होता जायेगा और जो वे चाहते है वह होगा। वे आलोचना करें, इनके लिए उन्हें अधिकार है किन्तु विध्वंसक कार्य न करें। शिक्षा जो भविष्य की निर्मात्री है और भारत के भविष्य की रचना करने वाली शक्ति है, उस शक्ति को चोट चपेट न लगायें, यही मेरा उनसे कहना है।

इस प्रकार के साथ मैं शिक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं और विश्वास करता हूं कि जो प्रश्न मैंने उठाये है, उन का समाधान मंत्री जी देंगे।

श्री चन्द्र भाल मनी तिवारी (बलरामपुर) : सभापति जी, आज हमारे सामने जो चर्चा चल रही है इसमे यह नहीं कहा जा सकता कि इसकी महत्ता कम है लेकिन आज तक जो कुछ हुआ है वह मैं समझता हूं कि खिलवाड़ हुआ है और एजूकेशन मे जो बढ़ोत्तरी चाहते है वह नाम मात्र की रही है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। सन् 1959 मे नई दिल्ली मे आर्कीटेक्चर के प्लानिंग स्कूल की स्थापना हुई थी। उसको रूरल और अर्बन दोनों एरियाज को डेवलप करना था लेकिन आज वह नाम मात्र के लिये है और दिल्ली और उसके कुछ स्थानों तक सीमित है। साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि जो ध्यान नहीं दिया गया है तो इस पर क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कोई सीमित समय रखा जाएगा जिसमे इस पर विचार होना और कार्यान्वयन होना आवश्यक समझा जाएगा।

इसके बाद मैं आजकल की जो एजूकेशन है, उस पर ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज जो हमारे वकील साहबान शिक्षा के माध्यम

[श्री चन्द्र भल मनी तिवारी]

से अपना प्रोफेशन करते हैं, उसमें जो इन्टर-प्रीटेशन उनका है, जो ला का इन्टरप्रीटेशन है, उसकी सत्यता कहां जा कर रूकती है और उसके क्या नतीजे निकलते हैं । क्या इसमें कोई संशोधन, शिक्षा प्रणाली में कोई संशोधन या कोई उपयोगी चीज लाना चाहते हैं या नहीं । वकील बनाना आवश्यक है लेकिन साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि ऐसी शिक्षा न दी जाये, जिससे किसी भ्रमात्मक रास्ते पर लोग पहुंच जायें । आज देश में जो टीका टिप्पणी हो रही है चाहे हमारे संविधान की हो या हमारे देश की समाज की या जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं उसकी हो मैं देखता हू कि इस बात से सभी सहमत हैं कि अदालतें अलग-अलग तरह के फैसले देती हैं, एक अदालत कि चीज के बारे मे एक फैसला देती हैं तो दूसरी अदालत उसको काट देती है । ऐसा क्यों होता है ? इसको खत्म होना चाहिये और प्रणाली मे अगर काई दोष है तो उसको दूर किया जाना चाहिये ।

उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश दिया है कि नये स्कूलों तथा नये कालेजों को मानवता दी जाय । सरकार तो नए स्कूल कालेज खोलने में सक्षम नहीं है लेकिन अगर कोई खोलता है दूसरा तो उसको मान्यता भी नहीं देती हैं । यह चीज उस एरिया के लिये जहां पर स्कूल कालेज नहीं है एक दुर्भाग्य की बात हैं । प्रोइवट इंस्टीट्यूशन अगर वहां जाती है खोलने के लिये तो क्यों उसको मान्यता न दी जाये इस पर आपको दुबारा सोचना चाहिये और मैं आशा करता हूं कि इस पर आप प्रकाश डालें ।

कालेजों में कहीं-कहीं अंधेर हैं । मैनेजमेंट कमेटी मनमानी करती हैं । चांसलर्स और वाइस चांसलर्स को भी कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं । मैनेजमेंट कमेटी किसी टीचर या प्रोफेसर के काम में दखल देना चाहती है तो मनमाने ढंग से वाइस चांसलर के पास उस जोज को भेज कर ऐप्रूव करा लेती है । वाइस चांसलर किसी वजह से मैनेजमेंट कमेटी से प्रभावित हो तो उसका काम बन जाता है और रूल्ज एंड रैग्युलेशन का कोई लिहाज नहीं रखा जाता है । चांसलर भी आंख मूंद कर काम करते हैं । अवध यूनिवर्सिटी जो उत्तर प्रदेश की है फैजाबाद में वहां पर हमारे बलरामपुर के एक प्रिंसिपल के खिलाफ वाइस चांसलर ने कुछ मूवमेंट चला दी । इसका नतीजा यह हुआ कि जिनकी कोई गलती नहीं थी उनको ससपेंड करवा दिया गया । चांसलर महोदय भी उस पर मौन हैं । मैं मंत्री जी का ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इन तरह की मैनेजमेंट कमेटीज को भंग किया जाना चाहिये । इनके इस तरह के कार्य कलापों से जो सही रास्ते पर चलने वाले लोग होते हैं उनको अनावश्यक रूप से कष्ट सहना पड़ता है ।

खेलकूद के सम्बन्ध में भी मैं कुछ निवेदन करना चाहता हू । इसमें बहुत भाई भतीजा-वाद चलता है । इसका नतीजा यह होता है कि देश तथा विदेश में हमारी टीमे जो खेलने के लिये जाती हैं वे खेल का स्तर इतना ऊंचा नहीं कर पाती है जिससे भारत का नाम रोशन हो, भारत का सिर ऊंचा हो । यह भाई भतीजावाद दूर होना चाहिये ।

लड़कियों की शिक्षा के बारे में भी मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा । इनकी शिक्षा बहुत कम खर्च में हो जाती है । लड़के तो कुछ शरारतपूर्ण काम भी करते हैं लेकिन कन्यायें ऐसे काम नहीं करती हैं । ये बड़े शान्त स्वभाव की होती है और शान्त वातावरण

बरण में रह कर ही काम करती हैं। लड़कों के स्कूल तो हैं लेकिन लड़कियों के स्कूल तथा कालेज कम हैं। गर्ल्ज की संख्या हमारे देश में पचास प्रतिशत है। चूंकि इनके लिये स्कूलों तथा कालेजों की संख्या कम है इस वास्ते ये शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाती हैं। मेरी प्रार्थना है कि लड़कों के स्कूल तथा कालेजों के समान ही लड़कियों के स्कूल और कालेज भी आप खोलें।

ट्रेनिंग कालेजों के बारे में भी मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। वहां एक चीज देखी जा रही है। ट्रेनिंग कालेजों मे नम्बर शिक्षा, योग्यता आदि का ध्यान रखे बिना ही कभी कभी दे दिये जाते हैं। उस ओर ध्यान न दे कर लग लगाव को ध्यान में रख कर उनको नम्बर दे दिये जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि सुधार के बजाय नाश ही अधिक होता है। वहा पर यह सबसे बडी कमी है। हमारे ट्रेनिंग कालिजेस में इसकी भरमार है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस पर अपना ध्यान दें।

हमारे कालेजेस में यूनियन्स की स्थापना हुई, लेकिन क्या यह सच नहीं है कि यूनियन बाजी से हमारे देश की सभी ऐजूकेशन्स सस्थायें नष्ट-भ्रष्ट हुई ? । आज इस बात के लिये मंत्री महोदय को बड़े विश्वास के साथ कहना चाहिये कि भविष्य में यूनियनें नहीं बनेंगी। अगर ऐजूकेशन को बढ़ावा देना है तो इसकी तरफ जरूर ध्यान देना चाहिये।

शिक्षा प्रणाली हमारे देश में क्या नौकरी के लिये बनी है ? जो कोई भी स्कूल या कालेज से शिक्षा प्राप्त करने के बाद निकलता है, वह नौकरी की तलाश करता है। लेकिन सरकार के पास इतनी नौकरी नहीं है। ऐसी पद्धति क्यों नहीं लागू की जाती है जिसमें नौकरियों की तलाश करनी पड़े ? मंत्री महोदय कहेंगे कि वह कौनसी पद्धति है ? मैं साफ तौर पर अर्ज करना चाहता हूं कि घरेलू उद्योगों की तरफ ध्यान देना चाहिये। आप जापान और जर्मनी को देख लीजिये, ये दो कन्ट्री ऐसे हैं जहां घरेलू उद्योग प्रारम्भ से ही बताये जाते हैं। उसमें बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं और अपने को इस योग्य बना लेते हैं कि वे सरकार पर डिपेंड नही करते।

मंत्री महोदय कालेज के तमाम अनुभवो को जानते है। आपने 2 साल पहले अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का बिल पेश किया था, लेकिन उसका नतीजा यह रहा कि देश में काफी उलझनें खड़ी हो गयी। अगर आज हिन्दू यूनिवर्सिटी के खिलाफ कोई बिल लाना चाहेंगे तो भी उलझनें खड़ी हो सकती हैं। मैं कहना चाहता हूं कि एक सा कानून देश में बनायें, चाहे वह हिन्दू यूनिवर्सिटी के लिये हो या मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिये हो। समान नियमों में हमारे देश के स्कूल, कालेजेस और यूनिवर्सिटीज चलें।

इस देश में अगर शिक्षा प्रसार करना है तो यह आवश्यक है कि जितने हमारे स्कूल, और कालेज हैं, जब उनका पेमेंट और तनख्वाहें सरकार देती है तो यह क्या जरूरी है कि उनका मैनेजमेंट दूसरों के हाथों से रहे ? सरकार को मैनेजमेंट अपने हाथों में लेना चाहिये।

इस प्रकार से मैं इस मंत्रालय की मांग्स का अनुमोदन करता हूं।

श्री जगन्नाथ मिश्र (मधुबनी) : सभापति महोदय, लोग समझें या न समझें, लेकिन वह कहने में हिचक नहीं रखते कि शिक्षा समाज को रीढ़ है। लेकिन यह रीढ़ कैसे कायम रह सकती है, इस पर बहुत थोड़े

[श्री जगन्नाथ मिश्र]

लोग विचार करते हैं, बल्कि मैं यह कहता हूं कि जिन पर इनका दायित्व है, वह भी बहुत कम माथा इस पर लगाते है। उसका नतीजा स्पष्ट है।

हमने देखा है कि चन्द महीने पहले देश में जो अराजकता का वातावरण छा गया था, उसके पहले ही शिक्षा के क्षेत्र में भी वैसा ही वातावरण आ गया था। स्कूल, कालेज, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय कहीं भी देखिये उन संस्थाओं को शिक्षा से कोई ताल्लुक नहीं रह गया था बल्कि राजनीति से ही उनका सम्बन्ध हो गया था। एक यूनियन का चुनाव हो तो करोड़ों और लाखों रुपया उस पर खर्च होता था। एक कहावत है कि एक तो करेला दूसरा नीम-चढ़ा। हमारे देश में पहले से ही एक दूषित वातावरण बना हुआ था, लेकिन इस बीच में विरोधी पक्ष के लोगों ने ऐसा रवैया अख्तियार किया, और जिस तरह का वातावरण बनाया, उससे हमारे छात्रवर्ग में उच्छृंखलता और अनुशासनहीनता इतनी बढ़ गई कि हम हताश हो गये, और यह सोचने लगे कि जिस देश के नौजवान राष्ट्रीय से अराष्ट्रीय हो जायें, और जिस कर्त्तव्य के निमित्त वे शिक्षा संस्थाओं में आये हैं, उसको भूलकर दूसरा कोई धंधा अख्तियार कर लें, उस देश को भगवान ही बचाये।

लेकिन मैं प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी को धन्यवाद देने से नहीं थकता हूं कि उन्होंने ऐन मौके पर देश की स्थिति को समझा, उन्होंने देश में आपात स्थिति को लागू किया और 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को देश के समक्ष रखा। शिक्षा जगत पर इसका बहुत सुन्दर असर पड़ा। आज आप कहीं भी स्कूल, विद्यालय, कालेज, या यूनिवर्सिटी में जायें, तो आपको एक सुखद परिवर्तन दिखाई देगा, और आप यह सोचने पर विवश होंगे कि कुछ समय पहले हमारे देश में क्या हो गया था, क्या लोगों ने भांग खा ली थी, उनकी मनोवृत्ति ऐसी क्यों हो गई थी, और छः महीने के बाद अब यह परिवर्तन कैसे हो गया है। जहां पहले की स्थिति के बारे में कहते हुए मुझे खेद और दुख होता था, वहां वर्तमान स्थिति का वर्णन करते हुये मुझे तसल्ली और सन्तोष हो रहा है। मैं इस बात पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करना चाहता हूं कि शिक्षा जगत में हमको बहुत सफलता मिली है और हम और आगे बढ़ने के लिये तत्पर है।

इसलिये मैं मंत्री महोदय, जो बहुत मर्मज्ञ विद्वान है, उनके मंत्रालय और अन्य विद्या-विज्ञों से निवेदन करूंगा कि वह इस विषय पर गम्भीर चिन्तन करें और देश के सामने एक ऐसा सिलेबस, करीकलम और कार्यक्रम पेश करें, जिससे अध्यापक सहमत हों, और हमारे देश के बच्चों को उसके आधार पर ढालने की कोशिश करें।

श्री मूल चन्द डागा : एजूकेशन एक स्टेट सबजेक्ट है।

श्री जगन्नाथ मिश्र : अगर माननीय सदस्य भी इन बातों को नहीं समझते रहे हैं, तो हमारे छात्र कैसे समझ पायेंगे ? हमारे मंत्री महोदय बार-बार नेशनल पालिसी आन ऐजूकेशन की बात कहते रहे हैं। मैं उसी के परिप्रेक्ष्य, कनटेक्स्ट, में बात कर रहा हूं। इसीलिये मैंने कहा कि हम उदासी और परेशानी की भावना को छोड़कर एक ऐसा कार्यक्रम देश के सामने रखें, जिसको हमारी शिक्षा संस्थायें, अध्यापक और छात्र स्वीकार करें, और हमारे बच्चों की तरक्की हो। हमारे बच्चे भविष्य के मालिक हैं-देश का भविष्य उनके साथ जुड़ा हुआ है। अगर उनकी तरक्की होगी, तो देश अग्रगामी हर क्षेत्र में तरक्की करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

इस पृष्ठभूमि में मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत सी जानकारियां हम लोगों को अभी भी नहीं हैं। हम लोग कुछ रूढ़िवादी हैं और रूढ़िग्रस्त मार्गों पर ही चलना पसन्द करते हैं। अगर कोई विदेश से पढ़ कर, वहां से कोई डिग्री या डिप्लोमा लेकिन, न आये, तो लोग समझते हैं—और वह स्वयं भी यह समझता है—कि वह कोई परिपक्व विज्ञान नहीं है और उसने कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। यह मिथ्या और बिल्कुल गलत धारणा है। हमारे यहां पढ़ने-पढ़ाने और सोचने-विचारने का काफी स्कोप है। इस प्रसंग में मैं संस्कृत का हवाला दूंगा। अगर आप संस्कृति के पुराने ग्रन्थों को पढ़ें तो आपको यह जानकर हैरत होगी कि आज जिस विज्ञान की उन्नति और उत्कर्ष की चर्चा करके हम प्रसन्न होते हैं और कभी-कभी आश्चर्य-चकित भी होते हैं कि विदेश के लोगों ने ऐसी उन्नति कर ली है, हमारे इन ग्रन्थों में वे सारी बातें भरी पड़ी हैं। उन बातों को आप हमारे इन ग्रन्थों में पढ़ेंगे तो आप स्वयं सोचेंगे कि हम कहां बाहर घूम रहे थे, सारा ज्ञान-विज्ञान तो हमारे घर में है। मेरा निवेदन है कि अगर संस्कृत के ग्रन्थों का पठन पाठन हो तो हम विज्ञान की बहुत सारी बातें घर बैठे समझ लेंगे और सीख लेंगे जिससे देश को बहुत लाभ होगा।

अभी तिवारी जी ने शिक्षा के बारे में कहा कि हम ऐसी शिक्षा पाते हैं कि नौकरी के लिए चक्कर काटते हैं। उनका कहना बिल्कुल ठीक है। आजकल हमारी शिक्षा का लक्ष्य ही यही है कि हम पढ़ते हैं नौकरी के लिये। यह बिल्कुल गलत चीज है। हम लोगों के मन से कैसे इसको दूर करें यह एक समस्या है और शिक्षा मंत्री महोदय के लिए तो यह एक जबर्दस्त समस्या है ही। मैं अपने विचार से कहूंगा कि हमारी शिक्षा पर खूब चिन्तन हो और हम शिक्षा को एक ऐसा रूप दें, एक ऐसा ढर्रा दें, ऐसे सिलेबस और करीक्यूलम हम तैयार करें जिससे लोग पढ़ कर नौकरी ही न करना चाहें बल्कि जीवन में और भी बहुत से क्षेत्र हैं, और भी बहुत से मौके हैं, और भी बहुत से विभाग है जिनमें वे काम कर सकें जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं जाब ओरिएंटेड एजूकेशन। अगर हम पढ़ कर खेती करते हैं या व्यवसाय करते हैं या और कोई काम करते हैं तो यह मानी हुई बात है कि बगैर पढ़े लिखे लोग जो काम करते हैं उसमें हमारा काम अच्छा अवश्य होगा। लेकिन यह है विश्वास करने की बात। इसमें हम कहां तक विश्वास करते हैं? अगर हम किसी से यह कहने जाय तो वह कहेगा कि उसने तो पढ़ कर यह स्थान प्राप्त कर लिया और मुझे खेत पर जाने के लिए कहते हो। लेकिन इसको भी मैं रूढ़िवादी विचार कहता हूं और इसमें भी हमें परिवर्तन लाना है। यह हम सब के लिए एक चुनौती है जिसका हमें सामना करना है। अपने नौजवानों को हर काम के लिए मुस्तैद करना है। गांधी जी ने कहा था कि हमें काम को प्रधानता देनी है। हम किसी काम को छोटा न समझें। हर काम का अपना महत्व होता है, हमें यह सीखना और जानना है और अगर यह जानकर हम विद्या अर्जित करेंगे तो अवश्य उससे लाभान्वित होंगे और नौकरी के चक्कर में दफ्तर-दफ्तर मारे-मारे नहीं फिरेंगे।

मैं एक और विषय की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जब तब मैं अखबार में देखता हूं कि हमारे देश की जो बेशकीमती मूर्तियां हैं वे चोरी हो जाया करती हैं और जब वह चोरी हो जाती हैं तब हम आकाश पाताल एक करने लगते हैं।

[श्री जगन्नाथ मिश्र]

मैं आप से जानना चाहता हू कि आपने कोई ऐसा सर्वे किया है कि इस तरह की मूर्तियां देश मे कहां-कहां हैं और उनकी रक्षा की क्या व्यवस्था आप ने की है ताकि आगे से यह चोरी की घटनाएं न हो।

दूसरा मेरा निवेदन है, मेरे अपने विचार से सेकेंड्री स्टेज तक की जो शिक्षा है उस शिक्षा को बिल्कुल फ्री कर देना चाहिए क्योंकि आज लाख शिक्षा की प्रणाली न परिवर्तन हुए समाज मे जो गरीबी है और हर तरह के लोग हैं उनकी आय एक दिन मे या एक रात में तो नही बदल रहे हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि मैट्रिक तक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य कर दी जाय। ऐसा मेरा विचार है और इसके लिए मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूगा।

जहां तक भाषा का सबध है पं.डे जी ने कहा और ठीक ही कहा कि अभी भी हम पुरानी लकीर के फकीर बने हुए है। हम सोचते हैं कि बिना अंग्रेजी के हमारा काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर हम देश के बाहर पाव रखें तो खुद अपने ज्ञान पर शर्मिंदा हुए बिना नही रहेंगे जब हम यह जानेंगे कि मुट्ठी भर लोग भी अंग्रेजी नही जानते है। और फिर भी हमारे सिर पर यह लदी हुई है। हम यह क्यों नहीं कबूल करते हैं कि अंग्रेजी हमारे लिए जरूरी नही है। हम बिना अंग्रेजी के भी काम चला सकते है। जब हम रूस जाते है तो क्या रशियन भाषा की आवश्यकता नही पड़ती है, जर्मनी जाते हैं तो जर्मन की आवश्यकता नही पड़ती है या और देशो मे जाते हैं तो और देशों की भाषा की आवश्यकता नही पड़ती है? तो इसमें क्या हर्ज है कि हम अपनी ही भाषा पढ़ें—क्षेत्रीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा? उसको हम दिल से, हृदय से प्रश्रय दें और उसका हम प्रसार करें। जहां तक अंग्रेजी पढ़ने की बात है उससे मुझे कोई झगड़ा नहीं है। लोग जर्मन भी पढ़ते हैं, रशियन भी पढ़ते हैं, उसी तरह अंग्रेजी भी पढ़ सकते हैं। वह तो अपने-अपने विचार की बात है। जिसको जो भाषा जचे उसको वह पढ़े। लेकिन अपने देश मे शिक्षा का माध्यम हमारी अपनी भाषा ही हो यह हमारे लिए श्रेयकर होगा और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का कारण होगा। जब हम बाहर जाते हैं, बाहर के लोगों से बात करते हैं और यहा हम कहते हैं अंग्रेजी तो अंग्रेजी शब्द सुन कर ही उन्हें हम से घृणा हो जाती है। वे कहते हैं, मुझे ऐसा मौका मिला है जब कि बाहर के लोगों ने कहा है कि क्या तुम्हारे यहां कोई भाषा नही है जो तुम अभी तक अंग्रेजी ही लादे हुए हो। आप तो श्रीमन्, कई बार बाहर गये होंगे और शायद आपका भी अनुभव यही होगा। पढ़ लिख कर लोग बहुत सी भाषाएं सीख सकते हैं। गांधी जी जब कार्य क्षेत्र में उतरे तो उन्होंने बहुत सारी भाषाएं सीख ली। इसी तरह जो जितना भी उत्साही होगा, विद्या में जिसकी अभिरुचि होगी वह एक नही अनेक भाषाएं सीख सकता है। वह एक अच्छी बात होगी। लेकिन जहां तक कोर्स की बात है, स्कूल, कालेज और विश्वविद्यालयो की बात है वहां पर हम लोग रीजनल भाषा और राष्ट्रीय भाषा से मुख न मोड़ें। यह हमारा मंत्री महोदय से आग्रह है कि इस पर वह विशेष ध्यान दें।

विद्या प्रचार के लिए स्कूल कालेज ही काफी नही हैं। आजकल लोग मंदिर मस्जिद को प्रतिष्ठा देते हैं, मैं कहता हूं, आज के जमाने में मंदिर मस्जिद से भी बढ़कर वाचनालय हैं। हम चाहते हैं हर ग्राम स्तर पर कम से कम एक लाइब्रेरी की व्यवस्था हो ताकि वहां पर लोग अपना काम करने के बाद, सुबह या शाम जब भी फुर्सत हो, जायें और वहां पर धर्म ग्रंथ, सामाजिक ग्रंथ या आर्थिक ग्रंथ जिसमें भी उनकी अभिरुचि हो उसको पढ़ें। सरकार इस सम्बन्ध में उनकी मदद करे और वहां ठीक प्रकार से उसका संचालन हो तो इससे बड़ा फायदा हो सकता है।

श्रीमन्, मैं अपने क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं—मेरे यहां बलिराज गढ़ है। बलिराज बड़े दानी थे। उन का स्थान हमारे यहां है। लोगों ने अपनी ओर से उस स्थान की खुदाई की है और बहुत सारी चीजों को वहां से निकाला है। लेकिन सरकार की ओर से कोई मदद नहीं हो रही है। मैं बड़े विनम्र शब्दों में आतुर हो कर मंत्री जी से कहता हूं कि अपने एक्सपर्टस को वहां भेजें और देखें कि वहां पर क्या मदद हो सकती है और इस के सम्बन्ध में कोई निर्णय लें। यदि इस की जानकारी मुझे मंत्री जी दे सकेंगे तो बड़ी कृपा होगी।

मिथिला यूनीवर्सिटी के बारे में बराबर ग्रान्ट के लिये हम मंत्री महोदय को तंग किया करते थे। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मिथिला यूनीवर्सिटी के कब्जे में 300 एकड़ से अधिक भूमि आ गई है। राजा दरभंगा ने देने की कृपा की है। श्रीमन्, मैं आप को भी इन्वाइट करता हूं—आप साथ चलें, तो मैं आप को दिखाऊंगा कि उस यूनीवर्सिटी की कैसी अट्टालिकाएं हैं, कैसे भवन हैं। जो संस्था जन्म लेते ही इतनी सम्पन्न हो जाय, वह आप की कृपा से वंचित रहे यह कोई अच्छी बात नहीं है। आप उसे सैन्ट्रल यूनीवर्सिटी बना दें तो बहुत अच्छा होगा।

मैंने जैसा पहले कहा था कि बाद में निवेदन करूंगा—तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे नौजवान मित्र किस प्रकार से हमारे हाथ से और हमारे काबू से बाहर हो गये थे, लेकिन जब बीस सूत्री कार्यक्रम हमारे सामने आया तो वे भी उस में सम्मिलित हो गये। उन में सामर्थ्य है, केवल उन को रास्ते पर लाने की बात होती है। जब आप उन को बिगाड़ना चाहेंगे तो वे बिगड़ जायेंगे, बीस सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से अब हमने उन को सुधारना चाहा तो वे सुधर गये हैं। वे अब दावा करते है कि सब से आगे है। आज हमारे स्कूल, कालिज और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले लड़के पढ़ने के अलावा गांव में जायेंगे और गाव के लोगों के कामों में हिस्सा बटायेंगे। गाव की सफाई, सड़कों का निर्माण, वृक्षारोपण—इन सभी कामों मे वे लग गये हैं। इन कार्यों में वे इतने व्यस्त हो गये हैं कि और कुछ सोचने की फुरसत ही नही होती। यूनीवर्सिटी की ओर से इस बात का बहुत प्रयास किया हैं कि लड़कों को ऐसे कार्यों में इन्वाल्व किया जाय। इस के लिये नेशनल सर्विस स्कीम है, नेहरू युवक केन्द्र हैं—उन दोनों संस्थाओं मे यह काम बहुत व्यापक रूप से हो रहा है।

दूरदर्शन के माध्यम से देश के 2400 गांव में शिक्षा मंत्रालय के डायरैक्शन में उपग्रह द्वारा लोगों को शिक्षा देने का कार्यक्रम चल रहा है। बच्चों के लिये खास कर सुबह 90 मिनट का कार्यक्रम होता है। चार भाषाओं में उस कार्यक्रम को सिखाया जाता है जो बीस-बीस मिनट के होते हैं। लेकिन इस सम्बन्ध में मेरी एक आशंका —यह उपयोगी कार्यक्रम आप के और अमरीका के कोलाबारेशन से चल रहा है। इस की समाप्ति के चार महीने बाकी रह गये है। मेरी जानकारी है और आप भी जानते होंगे कि इस करार को दोबारा स्वीकृति नही मिल रही है। ऐसी हालत में 40 प्रतिशत गांवों को इस कार्यक्रम से वंचित कर देना होगा। इस लिये मेरा निवेदन है कि ऐसी व्यवस्था की जाय जिस से कोई भी गांव इस कार्यक्रम से वंचित न हो। लेकिन साथ ही उत्साह का यह भी कारण है कि ऐसा निर्णय लिया गया है कि 6 नये केन्द्र खोले जायेंगे और उन से 84 गांवों में दूरदर्शन के द्वारा पढ़ाई की व्यवस्था की जायगी। यह बहुत अच्छी

[श्री जगन्नाथ मिश्र]

बात है—वह भी न घटे और यह काम भी होजाय, इस से विद्यार्थियों का बहुत फायदा होगा।

शिक्षा मंत्रालय ने एक सब-कमेटी की नियुक्ति की है कि हम कैसे सुन्दर सिलेबस और केरिकुलब बना सकते हैं, जिस में और केरिकुलम बना सकते हैं जिसमें बच्चों का इन्वाल्वमेन्ट भी हो उस कमेटी ने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं—जैसे पर्सनल हैल्थ, बेदिंग, केअर-आफ-टीथ, केअर आफ-ईयर्ज एण्ड नोज, केअर-आफ-आईज, केअर-आफर-हेअर, करेक्ट ईटिंग हैबिट्स, एक्सर-साइजेज फार गुड हेल्थ, इत्यादि बातों की उस कमेटी ने अनुशंसा की है और कहा है कि बच्चों को इन चीजों की शिक्षा दी जानी चाहिये। सोशल हैल्थ के लिये भी उस कमेटी ने कहा है—कीपिंग सर उण्डिग्ज क्लिअर, फर्स्ट-एड, फैमिलियेरिटीज-विद-सराउण्डिग्ज - एट-स्कूल - एड-एट - होम,—इन बातों की शिक्षा बच्चों को दी जानी चाहिए इसी तरह से हर विषय के लिये जैसे साइन्स, बोटनी, जलोजी, आदि के लिये उन्होंने बहुत सुन्दर रिकमेण्डेशन्ज की है। अगर उन के आधार पर बच्चों को शिक्षा दी जाय, तो मैं समझता हूं कि हम लोग आज तक शिक्षा के सम्बन्ध मे जितना रोना रो रहे थे, उतने ही अब हम प्रसन्न हो जायेंगे। लेकिन इस में क्या प्रगति हुई है—ऐसा लगता है कि अभी तक शिक्षा मंत्रालय के पास इस के बारे में रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन जो रिपोर्ट अभी तक आई है उस से ऐसा पता लगता है कि स्कूलों और कालिजों में छात्रों की उपस्थिति में बृद्धि हुई है। छात्रों ने बीस सूत्री कार्यक्रम को अपना लिया है। अभी तक ये कार्यक्रम 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिये थे, लेकिन अब उस से भी ऊपर की उम्र के बच्चों के लिये हितकर होंगे— ऐसी जानकारी अभी तक आप के मंत्रालय में प्राप्त हुई है।

शिक्षा प्रणाली को जीवन, राष्ट्र और उस की आशांक्षाओं से घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित करना चाहिये। एजूकेशन कमीशन ने इस की बहुत अनुशंसा की है . . .

सभापति महोदय : आप किस को कोट कर रहे है ?

श्री जगन्नाथ मिश्र : अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं, आप से निवदन कर रहा हूं।

16.58 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

मैं निवेदन कर रहा था कि एजूकेशन कमीशन ने अनुशंसा की है कि इकानामिक और कल्चरल प्रगति होनी चाहिये। सरकार की नैशनल पालिसी आफ एजूकेशन बननी चाहिये। इसके साथ ही बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयत्न किया जाना चाहिये। शिक्षा और समाज मे सम्बन्ध स्थापित होना चाहिये। राष्ट्र निर्माण का काम शिक्षा का एक आवश्यक अंग होना चाहिये। शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति को चरित्रवान बनाये और विकास की प्रेरणा दे—इस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिये। स्कूल स्तर तक विज्ञान और गणित की अनिवार्य पढ़ाई हो। उद्योगों से टैकनीकल एजूकेशन और रिसर्च का परस्परिक सम्बन्ध हो—इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिये।

जहां तक वोकेशनल एजूकेशन का सम्बन्ध है—हमारे 10+2+3 फार्मूले में वोकेशनल एजूकेशन का स्थान है : अगर वास्तविक ढंग से उस की शिक्षा दी जाय तो आज जितनी हाय-तोबा नौकरी के लिये मच रही है, हर जगह नौ-वकेन्सी का बोर्ड दिखाई देता है, वह बदल कर हर जगह वान्टेड-वान्टेड लिखा रहेगा—ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। 10 वीं कक्षा तक गणित की पढ़ाई आवश्यक है। विज्ञान के पढ़ने से वातावरण और अनुभव में बृद्धि

होती है । भाषा तथा संस्कृति के अध्ययन से हमारे बच्चों का ज्ञान बढ़ सकता है—मेरा अनुरोध है सरकार को इन सब बातों की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिये ।

अन्त में, श्रीमन्, मुझे एक निवेदन करना है—आज देश के अन्दर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, हम लोगों की सभी आकांक्षायें तभी पूरी हो सकती हैं जब आप शिक्षा के विषय को अपने हाथ में ले लें । श्रीमन्, यह मेरा अन्तिम अनुरोध मंत्री महोदय से है । आप ने मुझे समय दिया, इस के लिये आप का बहुत धन्यवाद ।

17 hrs.

SHRI B. R. SHUKLA (Bahraich): Mr. Deputy-speaker, Sir, I rise to support the Demands for Grants relating to the Ministry of Education.

Sir, Compulsory, Free and Universal Education for children upto the age of 14 years is a Constitutional Directive. But so far, we have failed in the matter of implementing this directive because of reasons of lack of resources and because Education, below University stage, is a State subject.

While certain dialogues regarding the desirability and the necessity of changes in the Constitution are going on my submission is, Education should be made a subject to be included in the Concurrent List.

In the Publication regarding Performance Budget which has been circulated by the Ministry of Education, it has been stated that the Central Government has allocated Rs. 1 lakh per district for the spread of education in each of these districts.

It is also mentioned in the same report that many of these States have implemented the recommendations and that some States (like U.P., Rajasthan and Assam) have started the programme on a massive scale. I doubt the authenticity of this statement contained in this report. As far as I know, in U.P. such a scheme has not been introduced.

Sir, I belong to a district which is situated on the Nepal border. It has the misfortune of having the lowest percentage of literacy. But, it is a matter of regret that neither the Central Government nor the State Government has done anything so far in the matter of increasing the percentage of literacy there. No doubt, the limitations of the Central Ministry of Education are very great. But, all the same, I would request the Minister to see to it whether the current allocation of Rs. 1 lakh made for the spread of literacy in each of the districts throughout the country has been implemented in the district of Bahraich.

Sir, so far as the reforms in the examination system is concerned, I was informed that a Committee was appointed to go into the question. It is also said that the Committee has submitted its report and that the UGC has sent that report for implementation by the States. Now, Sir, it is a matter of regret that the recommendations of that committee have not been circulated to the hon. Members of this House. At least I may say that I am not in possession of such a report. It is learnt that that Committee has recommended certain reforms in examination system. I would venture to suggest, without having the advantage of going through the report and the recommendations of this Committee, some points regarding reforms in the system of Education.

Sir, the Education Ministry has had a very comfortable academic year, thanks to the proclamation of emergency.

[Shri B. R. Shukla]

There is complete peace and tranquality in the campus. The examinations are being held according to schedule. There is no violence in the campus. But still, it is a standing blot in our educational system that the examinations are conducted under the surveillance of the police force as if criminals are collected there for some nefarious purposes and the police help is therefore, sought. (*Interruptions*) That is the position even now because irresponsible elements have not stopped their activities in the campus! Therefore, the situation needs vigilance for some time more

In order to avoid the menace of mass-copying, I think that in the examination halls, the examinees should be allowed to bring in as many books as possible and as they like and the examiners and the setters should frame the question papers in such a manner that even with the consultation and perusal of books which the examinees carry with them in the examination, they will not be able to pass the examination unless they have utilised their time in studying properly during the academic session. Even in Munsif's examinations the text-books are allowed by the public Service Commission. Therefore, an objective test should be devised in a manner so as to eliminate the chances of copying. So, consultations should be allowed. Another thing that I want to stress on is this.

SHRI B. V. NAIK (Kanara): Why not legalise the mass-copying if you mean that?

SHRI B. R. SHUKLA: That will come to the same thing. That will not be of any advantage to the examinee unless he has properly studied the course. Every student upto Class X should be trained to recite the national songs like.

वन्दे मातरम्

जन गण मन

सारे जहां स अच्छा हिन्दुस्तां हमार।

And there should be some marks prescribed for the proper and accurate recital of these songs. These are very minor things. But these should be included as part of the curriculum.

Another thing to which I wish to draw the attention of the Hon. Minister is this. So far as women's education is concerned, it has been mostly neglected it has not made any marked headway in our country. When our country is now passing through a revolutionary era, it is of utmost importance that the women folk should be properly and adequately educated. The child learns its first lesson by starting his education with mother's milk and it ends its education only with its death. The mother should, therefore, be educated first and there is absolutely no provision and there is no implementation of hostels being constructed for women in the rural-side. Therefore, my submission is that adequate attention should be paid towards education of women.

As regards propagation of Hindi, from the literature supplied by the Ministry of Education, I find that no teachers were appointed for teaching Hindi in Tamilnadu. Tamilnadu was not only averse or allergic but also completely hostile to the spread of Hindi because of the DMK party as ruling party depended on compaign of hatred against the spread of Hindi Thanks to the intervention of the Central Ministry, that party is no longer in power. The Education Ministry should take immediate steps for appointing teachers for teaching Hindi in that neglected part of Tamilnadu. Therefore my suggestion is

that all the students in the Hindi-speaking areas should compulsorily read one of the Southern Indian languages like Kannada, Marathi, Gujarati, Tamil, Telugu and Malayalam. Similarly, general Hindi should be a compulsory subject in all those States which are non-Hindi speaking states. Proper encouragement in the shape of monetary benefit should be extended to those who belong to Hindi speaking areas and who pass the examination in non-Hindi languages. Similarly, those who are in South India, they should also be encouraged likewise.

Sir, many teachers have been arrested in connection with RSS activities. Government has failed to terminate their services uptil now and in some places they are still getting their remuneration. It is high time that their services should be terminated forthwith. Service rules should immediately be revised and if there is absence of any rule to terminate their services, new rules should be framed. Some educational institutions such as Shishu Mandirs were run by this Organisation. The management of these institutions has been taken over in some States at least in U.P. but these institutions were charging fee at the rate of Rs. 8 to 12 per month because they employed special type of teachers. Those teachers have been replaced by a cadre of ordinary primary school teachers. Education in these schools is of primary stage. Therefore my submission is that the management of Shishu Mandirs should not be allowed to charge any fee from the students because the special type of teachers are no longer serving there.

Sir, it is not possible to do justice to the Demands of the Ministry of Education because it is very wide in its scope. Therefore, in the end I would support the Demands of the Ministry of Education. I congratulate the Education Minister who is silently but steadily and vigorously working in the cause of the spread of education and also in its qualitative improvement. The introduction of 10+2+3 formula will go a long way to create quality, quantity as well as job opportunities for the vast millions in the country.

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली : (टिहरी-गढ़वाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं और इस संदर्भ में माननीय श्री नूरुल हसन जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि हमारी शिक्षा की नीति में आमूल-चूल परिवर्तन किया जाये। लगता है कि इन 27 वर्षों में शिक्षा की दिशा में हमारी कोई नीति ही राष्ट्रीय स्तर की नहीं रही है। एक तरफ तो विश्वविद्यालयों की संख्या में मशरूम ग्रोथ होती चली गई और दूसरी तरफ प्राइमरी एजूकेशन, बेसिक शिक्षा की उपेक्षा की जाती रही है। इसका परिणाम यह हुआ है कि जिस अनुपात से देश की जन संख्या बढ़ती जा रही है, उसी अनुपात से हमारे यहां कम शिक्षा पाने वालों की संख्या में भी वृद्धि हुई है और जिन्हें ऊंचे स्तर की शिक्षा मिली हुई है, उसमें पढ़े-लिखे बेरोजगारों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसलिये मैं समझता हूं कि शिक्षा को यदि सम्यक बनाना है तो इसे एम्पलायमेंट ओरिएंटेड बनाना पड़ेगा ताकि जो भी व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता है वह अपने पांवों पर खड़ा हो सके।

हमारे संविधान के आर्टिकल 45 में इस बात का प्रावधान किया गया था कि संविधान लागू होने के दस वर्ष के भीतर ही देश में 14 वर्ष की उम्र तक के प्रत्येक बालक व बालिका को अनिवार्य शिक्षा दी जायेगी। लेकिन इतने वर्ष के बाद भी हम देखते हैं कि उस लक्ष्य को प्राप्त करना तो दूर रहा हम पीछे चलते जा रहे हैं। इससे लगता है कि जो नीति उस समय निर्धारित

[श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली]

की गई थी उसके पालन करने में शिक्षा मंत्रालय के लोग किस तरह से उदासीन रहे हैं।

मैं समझता हूं कि जो लक्ष्य एजूकेशन कमीशन ने निर्धारित किये थे, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये युद्ध-स्तर पर काम करने की आवश्यकता है।

लड़कियों की शिक्षा के बारे में आपको विशेष प्रयास करना चाहिये। जैसा कि श्री मुकुल जी ने कहा है कि अगर एक परिवार में एक लड़की शिक्षित हो जाती है तो समुचे परिवार को शिक्षा सुलभ हो जाती है।

हमारे यहां तो एक तिहाई लड़कियां तो स्कूलों में नहीं जा पातीं हैं, और जो लडकियां पहली कक्षा में दाखिला ले भी लेती हैं, उनमें से 30 प्रतिशत पांचवीं कक्षा तक रह जाती है। इससे पता चलता है कि हमारे देश में लडकियों की शिक्षा के प्रति कितनी उपेक्षा बरती जा रही है।

हमारे देश के अलग अलग भागों में जो स्थिति हैं, हमको उस के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिये। उदाहरण के लिये सरकार ने हिमाचल प्रदेश, काश्मीर और उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में पढ़े-लिखे बेरोजगारों की एक फौज खडी कर दी है। वहां स्थिति यह है कि जिस लड़के ने दसवीं श्रेणी पास कर ली है, वह पहाड में नहीं रह सकता है, वह मैदान में चला जाता है। इस प्रकार पढ़े-लिखे लड़कों का पहाड से निष्क्रमण हो रहा हैं। पहाडों में जो वनस्पति, वन-सम्पदा और हार्टिकलचर है, अगर लडकों को उसके अनुरूप शिक्षा दी जाये, तो मैं समझता हूं कि वहां पर टिक सकते हैं और वहां पर उनकी शिक्षा सार्थक हो सकती है।

हाल ही में मैं अपने निर्वाचन-क्षेत्र, उत्तर काशी के कुछ भागों में गया था। वहां मैंने देखा कि एक जूनियर हाई स्कूल में चार अध्यापक हैं और तीन विद्यार्थि है कई ऐसे स्कूल हैं, जहां अध्यापक महीने में एक दिन—तनख्वाह के दिन—स्कूल में जाते हैं और बाकी दिन गोल रहते हैं। कोई देखने वाला नहीं है। इस समय शिक्षा एक स्टेट सबजेक्ट है। इसको सेंट्रल सबजेक्ट बनाना चाहिये और यह देखना चाहिये कि देश की भावी पीढ़ी का निर्माण किस प्रकार हो रहा है। आने वाली पीढ़ी हमको केवल इसलिये माफ नहीं करेगी कि हमने संविधान में इस विषय को एक स्टेट साबजेक्ट बनाया है। शिक्षा के सम्बन्ध में समुचित उपक्रम न करने के लिये आने वाली पीढ़ी हमको दोष देगी।

मैं समझता हूं कि स्कूलों में जो न्यूट्रीशन प्रोग्राम है, वह अधिकांशत: सफल नही हुआ है और उसकी काफ़ी आलोचना होती है। अव्वल तो उसके लिए पैसे का प्रावधान कम है, और जो प्रावधान है, उसकी व्यवस्था ठीक नहीं है। इस लिए यह आवश्यक है कि बच्चों के लिए पौष्टिक आहार की विशेष व्यवस्था की जाये।

1974 में एक नेशनल पालिसी फ़ार चिल्ड्रन की घोषणा की गई थी। हमारे प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक नेशनल चिल्ड्रन्स बोर्ड भी बना हुआ है। सरकार ने इस पालिसी के कार्यान्वयन के लिए जो धन का प्रावधान किया है, वह काफ़ी नही है। उसमें वृद्धि करनी चाहिए।

सरकार ने वर्किंग विमेन के होस्टल्स के लिए 60 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था की हैं और 40 प्रतिशत की व्यवस्था वालन्टेरी आर्गनाइजेशन्स ने करनी है। उन संस्थाओं के पास इतने साधन नही हैं कि वे 40 प्रतिशत धन सुलभ करा सकें। श्री अरविन्द नेताम नवयुवक हैं। इस लिए नवयुवतियों और

कॉमन मैन के लिए उनके दिल में दर्द होना चाहिए। उनको इस सम्बन्ध में वालन्टेरी एजेन्सीज पर अधिक भार नहीं डालना चाहिए। जिन शहरों की आबादी दो लाख है, उनके लिए यह व्यवस्था की गई है। मेरा अनुरोध है कि जिन शहरों की आबादी एक लाख है, उनको भी इसमें शामिल किया जाये।

1974 में स्पोर्ट्स मिनिस्टर्ज ने यह तय किया था कि स्पोर्ट्समैन बनाने के लिए ब्लाक लेवल पर 1500 यूथ तैयार किये जायेंगे। पिछले वर्ष जुलाई में पंचायत लेवल पर यूथ क्लब आर्गनाइज करने का निश्चय किया गया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस दिशा में क्या प्रगति हुई है। मैं मानता हूं कि नेहरू युवक केन्द्रों ने, जहां जहां वे हैं, अच्छा काम किया है और काफ़ी प्रगति की है। लेकिन उनका जाल बिछाने की जरूरत है। जब तक काम करने के लिए कोई एजेन्सी नहीं होगी, तब तक हम इस दिशा में प्रगति नहीं कर सकेंगे।

श्री अरविन्द नेताम से मैं यह निवेदन करूंगा कि स्पोर्ट्स के मामले में विश्व मे हमारी ख्याति बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए इस सम्बन्ध में देश का रुतबा बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। मैं तो यहां तक कहूंगा कि कबड्डी और खो-खो आदि हमारे स्वदेशी खेलों को न केवल अपने देश में लोकप्रिय बनाना चाहिए, बल्कि दूसरे देशों में भी उनको ले जाने का प्रयत्न करना चाहिए।

जहां तक आर्कियालोजी का सम्बन्ध है, मैं विभाग को बधाई देना चाहता हूं कि उसने बामियान, अफ़ग़ानिस्तान, में बिग बुद्धा और स्मालर बुद्धा की मूर्तियों की सफ़ाई और उनके प्रिज़र्वेशन की व्यवस्था की है। मैं चाहता हूं कि जिन जिन देशों में भारतीय संस्कृति के अवशेष मौजूद हैं, धरातल में छिपे हुए हैं, उनका पता लगाना चाहिए और उन देशों के साथ अच्छे सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित करने चाहिएं। बामियान ही नहीं, अफ़ग़ानिस्तान में तो बहुत काफी इलाका ऐसा है जहां कि भारतीय संस्कृति अभी तक दबी हुई पड़ी है। मैं समझता हूं कि इस दिशा में आपको अधिक काम करने की आवश्यकता है।

दूसरी बात—जो मूर्ति चोरों के और इस तरह के अन्य गिरोह काम करते हैं उनके लिए केवल कानून बनाने से काम नहीं चलेगा। आवश्यकता इस बात की है कि जनसाधारण को साधारण भाषा में इस बात की शिक्षा दें ताकि जन-जागृति पैदा हो। आपके मंत्रालय को क्या प्रान्तीय सरकारों को भी आज मालूम नहीं है कि हमारे देश के सुदूर इलाकों में, मेघालय और हिमालय के दूर-दूर के इलाकों में कितनी प्राचीन संस्कृति हमारी छिपी पड़ी है और मूर्ति चोर तथा इस तरह के समाज-विरोधी तत्व इन्हीं बातों का फायदा उठाते हैं, सरकार की अज्ञानता का और समाज की अज्ञानता का फायदा उठाते हैं और वे हमारे देश की बहुमूल्य धरोहर को दूसरे देशों में बेचते हैं।

अंत मे मैं एक बात वीकर सेक्शन के बारे मे निवेदन करना चाहता हूं। समाज कल्याण विभाग को शिक्षा मंत्रालय के साथ नत्थी किया गया है। एक तो मैं यह निवेदन करूंगा भारत सरकार से और माननीय मंत्री जी के माध्यम से प्रधान मंत्री जी से कि समाज कल्याण का एक अलग मंत्रालय होना चाहिए क्योंकि इतना बड़ा यह विषय है कि इस विषय पर हम न्याय नही कर पाते हैं न हम इस पर अधिक कुछ कह पाते है। मैं यह निवेदन आप से करूंगा कि आप अपने मंत्रालय की मांगों को या तो दो भागों में विभक्त करें या इसका एक अलग मंत्रालय स्थापित होना चाहिए।

[श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली]

अन्तिम बात मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहता हूं और वह यह कि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में जिस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था चल रही है उस शिक्षा व्यवस्था से इस समय तक तो नुकसान बहुत हो चुका है, आगे आने वाले समय में बहुत अधिक नुकसान होने की संभावना है। आज की शिक्षा से एक प्रतिशत बालकों को भी रोजगार नहीं मिल पाता है। सब प्रान्तों में प्रान्तीयता की भावना विद्यमान है। इस कारण हमारे इन इलाकों का आदमी बाहर रोजगार पाने के लिए, काम्पीटीशन में आने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा कर भी कहीं आ नहीं सकता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि पहाड़ की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनकी शिक्षा का इंतजाम किया जाना चाहिए और उपाध्यक्ष महोदय, आप का क्षेत्र भी उसी प्रकार का है, आप भी महसूस करते होंगे कि किस प्रकार की शिक्षा वहां की परिस्थितियों के अनुकूल वहां के नवयुवकों और नवयुवतियों को मिलनी चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार की परिस्थितियां पहाड़ों पर हैं उनके अनुसार खास तौर से वन-विज्ञान है, सैनिक शिक्षा है, पशुपालन है, हार्टीकल्चर है, इन विषयों का प्रशिक्षण उनको देंगे तो यकीनन वहां पर शत प्रतिशत जितने बालक और बालिकाएं शिक्षा प्राप्त करेंगी उनको वहीं नौकरी मिल जायगी।

इन शब्दों के साथ मैं आपके मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं और आपको बधाई देता हूं कि आप ने इस वर्ष अधिक धन का प्रावधान किया है। मैं आशा करता हूं कि आज शिक्षा के क्षेत्र में जो परम्परा चलती आई है उसको तोड़ कर के संविधान में जो व्यवस्था की गई है उसको निष्ठापूर्वक कार्यान्वित कराने की दिशा में काम करें।

SHRI SATYENDRA NARAYAN SINHA (Aurangabad): Mr. Duputy-speaker, while discussing the demands on education, I must express my disappointment that the target date by which the constitutional obligation imposed on the government to provide universal free and compulsory primary education throughout the country has further receded According to the report that is in my hands, it appears that the target of universal education in the age group of 6 to 14 is likely to be achieved by 1986 and this delay or postponement or deferment in the achievement of the larget has been attributed to a heavy cut in the plan allocation or outlay on education. You are aware that the education ministry had prepared a plan involving an outlay of Rs. 3300 crores for the Fifth Plan and it was reduced to Rs. 2200 crores; later on it was slashed down to Rs. 1700 crores. Prof. Nurul Hasan has lamented that on account of the constraints imposed by finance, the goal set out in the Constitution remains distant.

It is a matter of regret because we are a welfare state and our goal is an egalitarion society. It is also admitted that education plays a very important part in social reconstruction, social change and also economic development. But whenever there is financial stringency, unfortunately the axe has always fallen and fallen heavily on the budget for education and other welfare schemes. I ask the Education Minister and through him the Government how far this is consistent with their professions that they want to bring about a welfare society and provide for the educational needs of the society, particularly the poor. It is imcumbent on any democratic society to provide education to the people in general, but unfortunately this has not been realised so far.

Much has been made of the fact that the emergency has brought about an atmosphere of calm and quiet which has enabled the Education Ministry to review the educational needs and requirements in consultation with various bodies and they have succeeded in evolving a national consensus with regard to the programme of action to implement the national policy on education which was placed before the House at the beginning of the Fifth Plan. The important programme is that of 10+2+3. You are aware, Sir, that this pattern has been before the government for a pretty long time. I would not refer to the recommendations of the Calcutta University Commission made in 1919, which included replacement of 10+2+2 by 10+2+3. The Radhakrishnan Commission appointed in 1948 recommended this formula of 10+2+3 adding a vocational bias. Before the Radhakrishnan Commission, the phenomenal progress made by Japan was considered to be a model and its industrial progress was attributed to the mass education programme undertaken by Japan. That is why this recommendation was made. In 1952 the Mudaliar Commission made the same recommendation. Again the Kothari Commission was appointed in 1964 and it submitted its report in 1966, which also contained this particular recommendation. In 1966 the Sampurnanand Committee on Emotional Integration appointed by the Education Ministry supported this recommendation. This Government has taken ten years to come to this conclusion. It was in 1948 that Shri Jawaharlal Nehru, while addressing the National Education Conference had expressed the hope that since a lot of changes had taken place in the country, the basis of education had to be revolutionised.

He had then said that whenever conferences or committees sat, they made certain recommendations but more or less, the *status-quo* had been maintained with minor modifications. He referred to the period before independence. But we have taken this decision now after 25 years of independence and the hope of Pandit Jawahar lal Nehru is going to realised now.

Now, it has been said that several States have already implemented this. As you are aware, when Mudaliar Commission made certain recommendations, there were certain States which adopted the recommendation of higher secondary pattern but U.P. and some other States stuck to their old pattern of education and they maintained their intermediate colleges. Now, the question is that in those States where following the Mudaliar Commission's recommendations, the pattern was changed, they have to revert back to 10+2+3 formula Secondly+2 is the whole crux of the formula and vocationalisation acquire importance. I would like to know whether sufficient spade work has been one or not? The Report says that they expect only 900 schools to adopt this course and they expect that by the end of Fifth Plan period this formula or this pattern of education will be introduced in all the States. The question is, what is the present position? The secondary education has always been the weakest link in the whole educational system. These schools should have trained teachers and other equipments. Now you are going to ask them to take up some kind of vocational system of education. The NCERT has been charged with the job of preparing the syllabus. I understand that they have already drawn up a big syllabus including therein 3-language formula physical sciences, social sciences, mathematics and a variety of subjects. And then the intention is to teach the bodys at the +2 stage some skill or craft. For many of them it is going to be a terminal stage. Has sufficient preparation been made for this purpose to equip these schools to take up this

[Shri Satyendra Narayan Sinha]

vocational course? The Education Minister told in 1974 while replying to the Education Budget that he had appointed a Committee to carry on survey of districts to find out what kind of skills and what kind of jobs could be available in that particular area so that education could be co-related with the skills and the jobs available, there because if you are going to make education employment oriented, it does not mean that you give them some kind of training and they get jobs. We have to create employment opportunities and give them requisite training to be absorbed in these jobs. The point is that this kind of education should go hand in hand with industrialisation so that you can have some coordination with the industry or with the Ministry of Labour which knows which kind of job requirement is going to have and then, you have to make provision for that. I would like to know whether that district survey has been over or not because I do not find any mention of this in this Report. Secondly there was the third all India survey which was conducted under the auspices of the NCERT and they have made a report that out of 5,92,088 schools in 1973, 6805 are Higher Secondary and 2983 are junior colleges. Now, so far as 2,983 junior colleges are concerned, perhaps, we may not find much difficulty in switching over to that formula of 10+2+3 with provision for vocational education. All that is needed is that we may have to provide them with equipments and with trained teachers for the kind of work that they are called upon to do. But you will have to convert 6805 higher secondary schools, to equip them to be able to take up the new responsibility which will devolve on them as a result of the introduction of the 10+2+3 pattern, with a vocational plank added to it. This is the position to-day. I do hope that when the Minister of Education replies to the debate, he will particularly enlighten the House as to the spadework that has been done, the prognosis about the data by which he expects its introduction, the time that will be taken in introducing this pattern; and also clarify as to what will be the position of those States which had already switched on to the higher secondary classes, how are the multi-purpose schools going to switch on to it, how much money you are going to provide—because you are asking them to revert to it—and to what extent you are going to have stability about this pattern. I do not gest that there should be rigidity or in flexibility. But I would suggest that there should be some kind of an assurance that this pattern when introduced will stay. I am inclined to believe that this uniform pattern will be introduced through out this country because the Emergency has given you some powers by which you can call upon the States to fall in line. And the CABE has also come to this decision. But the decision would not have made any change, but for the fact that the emergency has provided you with whipping hand. Secondary the Swaran Singh Committee has already recommended that Education should be made a concurrent subject. This is long overdue. It should be incorporated into the Constitution, so that you may have the authority to in troduce change, or to get your National Education Policy implemented.

With regard to the examination reform, I would say that there is a lot of confusion. It has been decided that nobody should fail at the higher secondary stage. "Pass for all" is the formula. It is also sugested that people will be allowed to take the competitive examination at this level and after recruitment, they will be given some in-service training. It was

mentioned that at the higher educational level, viz. universities and colleges, the grading system was being introduced. An internal evaluation system was also suggested. Various kinds of suggestions were made with regard to examination reform. Just now, Mr. Shukla had also made a suggestion that the examinees should be permitted to take books to the examination hall, to consult them if they needed. I would like this particular problem to be gone into at a greater depth and a solution found. Some criticisms have been levelled with regard to the grading system. It is suggested that the grade will be given subject-wise. Suppose I go to somebody seeking appointment. How will he assess my merit?

It is said that there will be no grade on the basis of aggregate mark but it will be subject-wise. Similarly on the evaluation system the people say that if there should be a subjective assessment, it will not be very satisfactory. But you can jolly well put some kind of norms. Well, there is the question of having question banks. So, there are various suggestions afloat, and I do wish that the Ministry of Education should once more come out with a clear policy in this respect.

I had expected that by the decisions which have been taken all kinds of confusion in regard to educational policy would have come to an end. But the Prime Minister, while addressing various conferences of late, has expressed her views very categorically about education. She has said she believes in experimentation, she believes that people should develop their own education, she does not believe in regimentation or nationalisation. On the other hand, you have seen that shri Jagjivan Ram and Shri Gujral have come out with the statement that education should be nationalised. We do not know where we stand. The Education Ministry will be able to clarify the situation and say what nationalisation means and what is the policy in this regard?

One word more and I will conclude. Education, if at all imparted in the way it should be, besides anything else, also helps develop our capacity to think critically, to understand, to communicate with each other, to express ourselves fearlessly. The question is whether there is the proper atmosphere where you can impart proper education, because I have been seeing all kinds of conferences being held by persons who claim to be pro-establishment, whereas the Prime Minister has said that she does not want "established establishment". She want freedom to criticise the administration to make it more dynamic; she wants that education be left free. So, I would once again ask that in view of our apprehension that there is a kind of atmosphere of fear and intimidation whether it would be possible to impart the right kind of education which would develop the capacity to understand and think critically.

SHRI RANABAHADUR SINGH SIDHI): Sir, I rise to support the Demands for Grants of the Education Ministry. It may be well understood that in the last 25 years of independence we as a people have been trying to undo what has been a purposeful under-mining of our national character by somebody who wanted to rule over us. That we are still far from achieving our objective is quite obvious from the debate we are witnessing today. Almost everyone who has spoken has said that we need change. Everyone is aware of the fact that what we have as a heritage in education does not cater to the needs of a country like ours.

There have been suggestions galore, and I do not want to cover that ground again, but in this context I have to plead only one point. This country has been full of a heritage

[Shri Ranabahadur Singh]

that has been much older than our recent accretions, a foreign attempt of giving this country a foreign heritage. And when I take your attention back to that period I say that where as the present education makes a man fit to think, makes a man fit to do a job, imparts him knowledge about the world, Indian education has always had the theory that the man should first know himself.

When suggestions are mooted as to how education should be brought in line with our country's needs. I am afraid this point has so far been missed. Certainly it does not fall into any curriclum in any educational institution in this country today. I think there must have been a time in this country when a boy who had just passed the kindergarten age must have been first told how to sharpen the tool of his mind before he was given other materials on which to work with it. It is surprising—not very surprising, but is not worthy—that now in the West people have started to think along these lines.

In this context, I would mention a book that has taken the USA by storm. It has been first on the best seller list for the last one year. It has been written by a doctor called Norman Harris, and its title is very misleading, "I am O.K. and you are O.K.". This Book, I think, hold out a promise for us, a secular State, to go about this task of giving our children at the age proper the wherewithal to sharpen the tools of their mind.

This book has also set the trend of education in the USA where, by psycho-analytical training, youngsters and even others become far more efficient people for the benefit of the country and for themselves. Such training would go a long way in alleviating our mostubiquitous problem of unemployment, because unemployment, as I look at it, is partly also due to the fact that a person has not been equipped to fix himself in any place on his own efforts.

At the present moment, our total educatioinal background makes a person of such a frame of mind that he has no option but to search for an opening in an establisment where a job—whether he is suited to it or not, it should carry a monthly emolument—is available. So, I would plead that our Education Minister, at whose dedicated and gracious hands I am sure this Ministry will go a long way in solving this problem, should also have some people study the possibility of the application of such an education in our country.

For example, I would say that our educational system is rather tardy in giving vocational skills to our young people, and a case in point is the big coal mines in the Singrauli Mines in the District of Sidhi in Madhya Pradesh. Here, there are huge machines that have to be operated by people with a little skill, and these people are hard to come by. At the same time this district has at the present moment 20,000 unemployed people on the rolls of the employment agency. It is almost a case of water, water everywhere but not a drop to drink. When I asked how is it possible that these people who are educated—there are B.Scs and M.Scs—to operate these shovels and dumpers of the NCDC in these coal dumpers of the that there was no such institution in the country today which could give them this skill. This is what I would like to say: offer scope to tailor our education to our industrial needs.

It has also been our ill-fate that ours is a backward region. Most of the faculty people in our areas are not willing to serve in such areas where the facilities available are not of the same level as they can get at other urban areas. Whereas there are posts lying vacant in our medical colleges, in our engineering colleges, and whenever any well-educated person is

posted to these posts, he finds a way out and our backward region is deprived of these faculties of education.

Another difficulty that we are facing is the difficulty of the managements in our universities. Invariably, all those universities have been running on the lines of the management boards in which there are some nominated and some elected members. It has been constantly the uniform pattern in almost all these management boards that there are some members who are elected by the graduate electoral college and these elected members owe their election to the graduates who invariably form the staff of such universities and, inivariably, pressure is brought upon the management of the university by these elected graduates to tailor the laws to suit the staff rather than the students. The dog-fights that ensue in each management meeting are a shame on any educational institution. I would plead that the laws that govern the constitutions of these management boards should have have another examination for how they could be revised to oviated such unseembly and really unhelpful affairs.

Rewa is a small town in north-east of Madhya Pradesh. Close-by Rewa, there is a place called Gurgi. It is one of the richest archaeological areas of that place. The Avadhesh Pratap Singh University has sought this Ministry's clearance to carry out excavations in that area. The Archaeological Department in the Banaras Hindu University has very kindly agreed to help the Rewa University to carry these excavations out. I would plead with the hon. Minister to allow us to carry out these excavations because, apart from holding out a rich store of our national heritage, they would give the students of Rewa University a very welcome opportunity to do some archaeology on their own.

I would like to bring an observation of mine to the notice of this Ministry that last year, I had been to Onkareswar which is on the Narmada river, close to Indore. One has to cross the river by a ferry when one goes to have a *darshan* at the Shiva temple there. In the boat by which we were crossing the river there was a girl of about 9 or 10 years of age she asked all of us in the boat to take turns in throwing a rupee into the river and she would count ten after the rupees had hit the water and she would dive and retrieve it. We got interested and we found out that this girl had been picked up by the B. D. Os he had won the swimming competition in the whole division consisting of seven districts. Maybe, she would beat the Olympic champions if she is given proper training. There must be some sort of an organisation, an apparatus, which could pick up these pomising youngesters from the villages and bring them to a place where they could be given training. Maybe, they hold out our Olympic hopes.

Lastly, as this Ministry also covers the area of Culture, I have a suggestion to offer, which may be studied for what it is worth, whether it will be possible to carry out an exercise whereby all the different dialects of this country, which are numberous to say the least, could be written in the Nagiri script. By doing so, the Nagiri script could provide the integrating link for the whole country.

SHRI Y. S. MAHAJAN (BULDANA): Mr. Deputy-Speaker, Sir, substantial progress has been made in the field of primary education. There is no doubt about that. The enrolement in the age group 6—11 has increased to 83 per cent by 1974-75, and it is estimated that, by 1978-79, that is within three years, the target of 97 per cent enrolement will be achieved.

[Shri Y. S. Mahajan]

This statistical picture is however, largely misleading because our schools are not able to retain the students who join them in the First Class. The number of those who stagnate and drop out comes to nearly 60 per cent of the total, and those who drop out relaps into illiteracy, with the result that the number of illiterates in the country today is much more than what it was in 1947|

Apart form the finance necessary for making primary education universal and compulsory, there is also the problem of providing inducements to students and of making the system efficient and attractive. Even a child really learns something which is apparently useful or not, it is bound to be attracted to the school because learning or acquiring knowledge is a process which is a source of delight. In this process, the primary school teacher has a significant role to play. He should be not only a social worker but also a dedicated teacher. I wonder how many of them are able to act like magnets by reason of their love for childern and excellence of teaching I suggest that the Ministry of Education or the NCERT might undertake a research project to find out how many primary school teachers get themselves transferred to their villages or in the neighbourhood and carry on agricultural or other avocations and neglect their duties. I hope, the hon. Minister will undertake such a study.

To leave a large and growing number of our people in a state of illiteracy, which means the same thing as ignorance in our country, amount to an uttar failure on the part State in its primary duty to its citizens. In the words of the great philosopher, Hobbes, without education or without knowledge life is. short, nasty and brutish. May I quote here also the words of a great scientific humanist, Prof. Julian Huxley? He says:

"Knowledge is basic. It is knowledge which enables us to understand the world and ourselves and to exercise some control or guidance. It sets us in fruitful and significant relations with the enduring processes of the Universe. And by revealing the possibilities of fulfilment that are still open, it provides an overriding incentive. We, the mankind contain the possibilities of the earth's immense future and can realise more and more of them on condition that we increase our knowledge and our love."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Member will continue tomorrow.

---

18 hrs.

STATEMENT RE ANSWER TO SQ. NO. 533 REGARDING BIRTH PLACE OF LORD BUDDHA

MR. DEPUTY-SPEAKER: Prof. Nurul Hasan to make a clarificatory statement.

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (PROF. S. NURUL HASAN): Mr. Deputy-Speaker, Sir, with your permission, I would like to mention that this morning while I was replying to a starred question regarding the birth place of Lord Budha, an hon. Member expressed the doubt that my colleague Shri D. P. Yadav had made a contrary statement in the House.

The facts are that while replying to an unstarred question No. 2337 dated April 12, 1976 which was laid on the Table of the House on April 14, 1976, my colleague had said:

"The discovery of a large number of sealings from a monastry at Piprawah District Basti in Uttar